

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी - ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 316/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मृतक भोप सिंह पुत्र जैसिह के कायम मुकामानः— 1/1 श्रीमती उसम कंवर बेवा भोपसिंह 1/2 लखेसिंह 1/3 भैरूसिंह 1/4 कल्याणसिंह 1/5 सुमेरसिंह 1/6 इन्द्रा कंवर वारिसान श्री भोपसिंह 2. शम्भूसिंह पुत्र जैसिंह 3. भीकसिंह पुत्र जैसिंह निवासीगणः— दी गांव, तहसील व जिला जालोर।		1. श्रीमती सकू कंवर पुत्री करणसिंह निवासी— सियाणा, जालोर 2. मेतीसिंह पुत्र करणसिंह निवासी— दीगांव, तहसील जालोर। 3. सरपंच, ग्राम पंचायत दीगांव, तहसील व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 10.06.2015 जो कि उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा अपील संख्या  
07/2011 बअनुवान सकू कंवर बनाम भोपसिंह में पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 331/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मृतक भोप सिंह पुत्र जैसिह के कायम मुकामानः— 1/1 श्रीमती उसम कंवर बेवा भोपसिंह 1/2 लखेसिंह 1/3 भैरूसिंह 1/4 कल्याणसिंह 1/5 सुमेरसिंह 1/6 इन्द्रा कंवर वारिसान श्री भोपसिंह 2. शम्भूसिंह पुत्र जैसिंह 3. भीकसिंह पुत्र जैसिंह निवासीगणः— दीगांव, तहसील व जिला जालोर।		1. श्रीमती सकू कंवर पुत्री करणसिंह निवासी— सियाणा, जालोर 2. मेतीसिंह पुत्र करणसिंह निवासी— दीगांव, तहसील जालोर। 3. सरपंच, ग्राम पंचायत दीगांव, तहसील व जिला जालोर।

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर  
वगैराह

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 10.06.2015 जो कि उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा अपील संख्या  
06/2011 बअनुवान सकू कंवर बनाम भोपसिंह में पारित किया।

उपस्थिति:-

1. श्री चैनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री आर०के० राठी, रेस्प० संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित
3. शेष रेस्प०डेन्टस बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:- 21 अगस्त, 2018

उपरोक्त दोनों अपील प्रकरणों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु एवं विचारणीय तथ्य एक  
समान होने से दोनों अपीलों का निर्णय संयुक्त रूप से किया जा रहा है। निर्णय की  
एक-एक मूल प्रति प्रत्येक अपील के संलग्न रखी जावें।

अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम  
दीगांव तहसील जालोर के खेत खसरा संख्या 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,  
721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 कुल रकबा 6.77 हैक्टर भूमि आई हुई  
थी। जिसके पूर्व खसरा नम्बर 223, 224 एवं 225 है। उक्त खेत खसरान की कृषि भूमि पूर्व  
में पक्षकारान के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज थी। अजीतसिंह की  
मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72  
दिनांक 14.8.1971 को भर कर स्वीकृत कर दिया गया।

इसी प्रकार अन्य खेत खसरान संख्या 177, 184, 217, 218 कुल रकबा 3.04 हैक्टर  
भूमि आई हुई थी जिसके पूर्व खेत खसरा संख्या 74 मीन, 74 मीन, 97 मीन, 97 मीन, 97  
मीन थे। उक्त खसरान भूमि पूर्व में अपीलान्टस व रेस्प० के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के  
नाम से आई हुई थी। अपीलान्टस एवं रेस्प० संख्या 1 व 2 सगे भाई है। अजीतसिंह की मृत्यु  
पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 17  
दिनांक 24.08.1960 को भर कर स्वीकृत कर दिया गया।

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर  
वगैराह

उक्त स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 72 एवं 17 के विरुद्ध वर्तमान रेस्पो संख्या 1 व 2 के द्वारा दो अलग-अलग प्रथम राजस्व अपीलों उपखण्ड अधिकारी जालोर के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा निवेदन किया कि उनके पूर्वज अजीतसिंह के वारिसान की हैसियत से करणसिंह व जैसिंह के नाम उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण में आने चाहिये थो लेकिन ग्राम पंचायत दीगांव के द्वारा अजीतसिंह व करणसिंह के समस्त वारिसान की बिना किसी जॉच पडताल के ही नामा० स्वीकृत कर दिया जो नियम विरुद्ध स्वीकृत होने से निरस्त किया जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई किये जाने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 10.06.2015 के द्वारा दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72 एवं 17 पर पारित आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार जालोर के इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे मृतक अजीतसिंह व करणसिंह के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण पारित करे।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी जालोर के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपीलान्टस के द्वारा द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। जिस पर दोनों पक्षकारान की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा की बहस को सुना गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उनके समक्ष प्रस्तुत हुए तथा उपलक्ष्य साक्ष्यों व सामग्री को न तो सही ढंग से समझा गया और न पढा गया था ऐसे में उपलब्ध सामग्री के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी क्योंकि अपीलाधीन नामा० संख्या 72 दिनांक 14.8.1971 एवं नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 24.08.1960 को स्वीकृत किया गया था, जिसके स्वीकृत होने के लम्बे समय यानि 40 से 50 वर्ष उपरान्त चुनौती प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की माता को भी प्रथम अपील में पक्षकार बनाया गया था जबकी उनकी पूर्व में ही मृत्यु हो गई थी ऐसे में पक्षकार बनाया जाना भी गलत था। ऐसे में प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद होने से खारिज किये जाने योग्य थी। रेस्पो० संख्या एक व दो आपस में भाई बहन है जिन्होंने आपस में संधि करते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें मोतीसिंह को आवश्यक पक्षकार ही नहीं बनाया था।

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर  
वगैराह

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को लोक अदालत के नाम पर दीगांव कैम्प में ले जाकर स्वीकार की गई है, जहाँ पर रेस्पोंडेंट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, अपीलीय अधिकारी की ओर से मात्र अपीलान्ट्स के अंगूठे करवाकर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि में पुत्रियों को विरासत का अधिकार वर्ष 2005 में हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बाद लागू किया गया है न कि उससे पूर्व में हुए बंटवाडा इत्यादि पर।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना चाहिये जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेंट संख्या एक सकू कंवर का विवाद काफी समय पूर्व ही ग्राम सियाणा में हो चुका था तथा वह अपने विवाह उपरान्त अपने पति के साथ ही ग्राम सियाणा में रहने लग गई थी ऐसे में वादग्रस्त भूमि पर उसका किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं था, तो उसके द्वारा प्रथम अपील में मनगढंत तथ्य लिखते हुए अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट्स को ब्लैकमेल करने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया था। जबकि रेस्पोंडेंट संख्या एक को उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमि में अपने हक-अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्व वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था क्योंकि नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिससे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त न ही हो सकते हैं और न ही दिये जा सकते हैं। इन सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये लगभग 40-50 पूर्व स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त करने में भारी भूल की है जिसे नियम विरुद्ध मानते हुए निरस्त किया जावे।

अतः अपीलान्ट्स की दोनों अपीलों को स्वीकार फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों दिनांक 10.6.2015 को निरस्त फरमाया जाकर नामा संख्या 72 एवं नामा संख्या 17 को यथावत बहाल रखा जावे।

रेस्पोंडेंट सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि उपरोक्त खेत खसरान की अंकित वादग्रस्त भूमि पूर्व में उनके पूर्वज उनके दादा

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर  
वगैराह

अजीत सिंह पुत्र तगसिंह की सहखातेदारी की भूमि थी। अजीतसिंह जी की मृत्यु उपरान्त उनके दो जायन्दा पुत्र अपीलान्टस के पिता एवं रेस्पोजेन्ट के पिता श्री करणसिंह एवं जैसिंह थे। जिनके नाम उत्तराधिकारी के रूप में समान रूप से भूमि हिस्सा होकर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 72 एवं 17 में आने चाहिये थे लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा उनके दादाजी के वारिसान की किसी प्रकार की जाँच किये बिना ही केवल मात्र जैसिंह यानि अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध व नियमों के विपरित जाकर स्वीकृत किया गया था। जिनकी जानकारी रेस्पोजेन्टस को होने पर उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अलग-अलग दो प्रथम अपीलें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, जालोर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

रेस्पोजेन्ट सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि सहखातेदार जैसिंह पुत्र अजीतसिंह की मृत्यु के बाद विरासत नामा० संख्या 192 दिनांक 22.1983 उसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है जो नामा० संख्या 72 स्वीकृत होने के बाद भरा गया था। अपने आप में गैर कानूनी होने से निरस्त करने योग्य था। इसके अलावा रेस्पोजेन्टस को उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज न होने की जानकारी लम्बे समय तक नहीं हो सकी जबकि उक्त खसरा भूमि में उसका भी कब्जा काश्त चला आ रहा था। इस प्रकार की रही त्रुटि की जानकारी होने पर उसके द्वारा अपीलान्ते नामा० आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करते हुए प्रथम अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा म्याद बिन्दू को कन्डोन करने हेतु भी निवेदन किया।

रेस्पोजेन्ट सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि किसी भी नियम विरुद्ध पारित किये गये आदेश के विरुद्ध चुनौती प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समय की बाध्यता आडे नहीं आती है तथा तथाकथित आदेश की जानकारी जिस समय हो, उसी समय से म्याद सीमा लागू होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के देहान्त हो जाने के उपरान्त उसके फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उसके सभी वारिसान की जाँच और उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार समान रूप से हक-हिस्सा अंकित करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये। जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत किये गये दोनों नामा० संख्या 72 एवं 17 को स्वीकृत किये जाने से पूर्व ऐसी कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई थी। अधीनस्थ

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर वगैराह

न्यायालय के द्वारा रेस्पों की ओर से प्रस्तुत किये गये इन्हीं आधारों पर अपीलों को स्वीकार करते हुए नामा० संख्या 72 एवं 17 को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार की जाँच कर नये सिरे से नामा० स्वीकृत किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं जो यथावत बहाल रखे जावे तथा अपीलान्टस की अपीलों को खारिज की जावें।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवताओं के द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया ग्राम दीगांव तहसील जालोर के खेत खसरा संख्या 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 कुल रकबा 6.77 हैक्टर भूमि आई हुई थी। जिसके पूर्व खसरा नम्बर 223, 224 एवं 225 है। उक्त खेत खसरान की कृषि भूमि पूर्व में पक्षकारान के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज थी। अजीतसिंह की मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72 दिनांक 14.8.1971 को स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार अन्य खेत खसरान संख्या 177, 184, 217, 218 कुल रकबा 3.04 हैक्टर भूमि आई हुई थी जिसके पूर्व खेत खसरा संख्या 74 मीन, 74 मीन, 97 मीन, 97 मीन, 97 मीन थे। उक्त खसरान भूमि पूर्व में अपीलान्टस व रेस्पों के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम से आई हुई थी। अपीलान्टस एवं रेस्पों संख्या 1 व 2 सगे भाई हैं। अजीतसिंह की मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 24.08.1960 को भर कर स्वीकृत किया गया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उनके समस्त वारिसान की जाँच कर, उन्हें अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त समान रूप से सभी वारिसान का नाम फौतेदगी नामा० में दर्ज करते हुए ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये जबकि अपीलाधीन दोनों नामा० संख्या क्रमशः 72 एवं 17 को ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व ऐसी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाना प्रतीत होता है तथा सहखातेदार अजीतसिंह के दो जायन्दा पुत्र जैसिंह एवं करणसिंह होने के बावजूद एक ही पुत्र जैसिंह के नाम से एकपक्षीय रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जिसे विधि अनुकूल उचित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवादित आदेश को, जो कि प्रारम्भ से ही शून्यता की श्रेणी में आता है, उसे किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी जालोर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाधीन नामा० संख 72 एवं 17 को निरस्त

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर  
वगैराह

करते हुए वादग्रस्त खेत खसरान भूमि के मृतक खातेदार के जायज वारिसान की जाँच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण पारित करने के जो आदेश पारित किये गये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलान्टस की दोनों अपीले स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जालोर के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 79/105 एवं 80/2015 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को सरे

इजलास सुनाया गया।



— " —